BCCI BULLETIN

Vol. 55 | March 2024 | No. 03

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार से मिलकर उन्हें बधाई दी

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा को पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से विचार-विमर्श करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल 21 मार्च 2024 को अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा से मिला और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

विद्युत टैरिफ में कमी से औद्योगिक विकास को मिलेगा बल : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिनांक 1 मार्च, 2024 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित विद्युत टैरिफ में वृद्धि न करके उसके टैरिफ में कमी के निर्णय का स्वागत करते हुए आयोग को धन्यवाद दिया है।

आयोग का यह निर्णय बिहार में औद्योगिक विकास को गति देगा। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने कहा कि आयोग ने बैठक में बताया कि विद्युत कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के विद्युत टैरिफ में 3.03 प्रतिशत की बढोतरी करने की मांग बिहार विद्युत विनियामक आयोग से किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि टैरिफ में कमी का मुख्य कारण डिसकॉम के सभी स्तर पर किए गए सुधार का परिणाम है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.3.2024)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

देश का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह फरवरी 2024 रुपये 1,68,337 करोड़ रहा जो फरवरी 2023 माह से 12.5 प्रतिशत अधिक रहा। बिहार का जीएसटी संग्रह रुपये 1491/– करोड़ रहा जो फरवरी, 2023 की तुलना में 1 प्रतिशत कम है।

लोक सभा चुनाव की तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा हो चुकी है। **ज्यादा नकदी लेकर चलने पर अपने साथ उसका आवश्यक प्रमाण साथ में अवश्य रखें ताकि पूछ–ताछ के दौरान आप परेशानी से बच सकें।**

15 मार्च 2024 से मंत्रीमंडल के विस्तार के साथ ही सभी मंत्रियों के विभागों की भी घोषणा हो चुकी है। चैम्बर की ओर से **माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री नन्द किशोर यादव, माननीय नगर विकास एवं आवास तथा विधि मंत्री, श्री नीतीन नवीन, माननीय सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा से मिलकर** उन्हें बधाई दी गयी। इससे संबंधित न्यूज इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

व्यवसायियों के लिए राहत की बात है कि अप्रैल 2024 से बिजली की दरों में बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से 2024 –2025 के लिए बिजली की दरों में बिजली कम्पनियों के वृद्धि के अनुरोध को स्वीकार न करके दरों में कमी की गयी है। इसके लिए आयोग को धन्यवाद। टैरिफ में कमी का मुख्य कारण डिसकॉम के सभी स्तर पर किये गये सुधार है। इसके लिए डिसकॉम को भी धन्यवाद। औद्योगिक उपभोक्ताओं को उम्मीद थी की **केवीए चार्ज में भी कमी की जाएगी। परन्तु इसमे कोई कमी नहीं की गयी है, जिससे औद्योगिक उपभोक्ताओं में निराशा है। उद्यमियों को अभी भी भरोसा है कि राज्य सरकार एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस आदेश पर पुनर्विचार करेंगे।**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्य व उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त सहित उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांग की गयी है कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर प्राकृतिक गैस की कीमतों पर लगने वाले वैट की दर को बिहार में भी घटाकर 5 प्रतिशत किया जाय।

समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार पटना में सीएनजी एवं पीएनजी सस्ती होने की उम्मीद है। पीएनजी, सीएनजी पर वैट 15 प्रतिशत कम करने का प्रास्ताव गेल इंडिया लिमिटेड ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को दिया है। **यदि इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो सीएनजी– पीएनजी की दरों में अवश्य कमी होगी, साथ ही चैम्बर की मांग की पूर्ति भी होगी।**

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 5 मार्च, 2024 को **नव पदस्थापित मुख्य सचिव, बिहार श्री बृजेश मेहरोत्रा, भा.प्र.से. से मिलकर उन्हें नव पदस्थापना की शुभकामनाएं दी। प्रतिनिधिमंडल में मेरे अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन शामिल थे।**

दिनांक 11 मार्च, 2024 को मैं चैम्बर के वरीय सदस्य श्री संजय कुमार भरतिया के साथ **बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नव पदस्थापित अध्यक्ष श्री अमीर सुबहानी, भा.प्र.से. से मिला और उन्हें नव पदस्थापना की शुभकामनाएं दी।**

न्यूनतम मजदूरी की दरें (अनुसूची–II) जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी, उसकी गजट अधिसूचना की प्रति सदस्यों को चैम्बर द्वारा भेजी जा चुकी है। माननीय सदस्यों की सूचनार्थ इस बुलेटीन में भी प्रकाशित की गयी है।

हर वर्ष की भांति दिनांक 22 मार्च, 2024 को चैम्बर में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। यह समारोह सदैव की भांति रंग, अबीर रहित थी। केवल गुलाब की पंखुड़ियॉ एक दूसरे पर डाल कर एवं होली की बधाई दी गयी। **होली मिलन समारोह में माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा श्री नन्द किशोर यादव जी, नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री नीतीन नवीन जी, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार जी, माननीय बिहार विधान पार्षद श्री ललन सराफ जी, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, उप महापौर श्रीमती रश्मि चंद्रवंशी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री ऋतुराज सिन्हा सहित पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बैंक के अधिकारी, अधिवक्ता, प्रमुख डॉक्टर एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने पधार कर चैम्बर परिवार को गौरवान्वित किया।**

होली मिलन समारोह को सफल बनाने में होली मिलन समारोह आयोजन समिति के संयोजक, सह संयोजक एवं सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही चैम्बर के माननीय सदस्यों के प्रति भी हृदय से आभारी हूँ जिनकी सपरिवार सहभागिता से समारोह भव्यता एवं हर्षोल्लास सहित सम्पन्न हुआ। होली मिलन समारोह की संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

सादर,

आपका

सुभाष पटवारी

महत्वपूर्ण सूचना

भारत सरकार ने पिछले साल प्याज के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध जो 31 मार्च 2024 तक था उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है।

इस संबध में विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 81 दिनांक 22 मार्च 2024 की प्रति माननीय सदस्यों को भेजी जा चुकी है।

अधिसूचना की प्रति हेतु चैम्बर कार्यलय से संपर्क करें।

महत्वपूर्ण सूचना

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सोना और चांदी आयात करने के लिए 11 बैंकों को अधिकृत किया है। तीन बैंकों इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में केवल सोना आयात करने के लिए अधिकृत किया है। उक्त संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी Public Notice की प्रति माननीय सदस्यों को भेजी जा चुकी है। Public Notice की प्रति हेतु चैम्बर कार्यलय से संपर्क करें।

दिनांक 15 मार्च, 2024 को बिहार के मंत्रीमंडल विस्तार के बाद माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों को आवंटित विभाग

क्रमांक	मंत्री का नाम	विभाग
1.	श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री	1. सामान्य प्रशासन 2. गृह 3. मंत्रिमंडल सचिवालय 4. निगरानी 5. निर्वाचन ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है।
2.	श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री	1. वित्त 2. वाणिज्य-कर
3.	श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री	1. पथ निर्माण 2. खान एवं भूतत्व 3. कला, संस्कृति एवं युवा
4.	श्री विजय कुमार चौधरी	1. जल संसाधन 2. संसदीय कार्य
5.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	1. ऊर्जा 2. योजना एवं विकास
6.	डॉ. प्रेम कुमार	1. सहकारिता 2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
7.	श्री श्रवण कुमार	ग्रामीण विकास
8.	श्री संतोष कुमार सुमन	1. सूचना प्रावैधिकी 2. लघु जल संसाधन 3. आपदा प्रबंधन
9.	श्री सुमित कुमार सिंह	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा
10.	श्रीमती रेणु देवी	पशु एवं मत्स्य संसाधन
11.	श्री मंगल पाण्डे	1. स्वास्थ 2. कृषि
12.	श्री नीरज कुमार सिंह	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
13.	श्री अशोक चौधरी	ग्रामीण कार्य
14.	श्रीमती लेशी सिंह	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
15.	श्री मदन सहनी	समाज कल्याण
16.	श्री नीतीश मिश्रा	1. उद्योग 2. पर्यटन
17.	श्री नीतीन नवीन	1. नगर विकास एवं आवास 2. विधि
18.	डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल	राजस्व एवं भूमि सुधार
19.	श्री महेश्वर हजारी	सूचना एवं जन-सम्पर्क
20.	श्रीमती शीला कुमारी	परिवहन
21.	श्रीमती सुनील कुमार	शिक्षा
22.	श्री जनक राम	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
23.	श्री हरी सहनी	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
24.	श्री कृष्णनंदन पासवान	गन्ना उद्योग
25.	श्री जयन्त राज	भवन निर्माण
26.	श्री मो. जमा खान	अल्पसंख्यक कल्याण
27.	श्री रत्नेश सादा	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
28.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	पंचायती राज
29.	श्री सुरेन्द्र मेहता	खेल
30.	श्री संतोष कुमार सिंह	श्रम संसाधन

चैम्बर प्रांगण में पधारे माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का चैम्बर पदाधिकारियों ने किया अभिनन्दन

दिनांक 18 मार्च 2024 को बिहार चैम्बर के प्रांगण में पधारे माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री नन्द किशोर यादव का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करते उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

साथ में हैं कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन भगत, श्री राकेश कुमार एवं श्री आशीष प्रसाद।

बिहार में सीएनजी-पीएनजी पर वैट की दर 5 प्रतिशत करने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य सरकार से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा कोयला और फर्नेश ऑयल से चल रही औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में बदलाव कराये जाने के दबाव के आलोक में मांग की है कि औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी पर लगने वाली वैट की दर को कम किया जाये।

वहीं गेल इंडिया ने भी सरकार को पत्र लिखकर सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए एक बार फिर पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि वैट कम होने से औद्योगिक यूनिट और आम लोगों को कम कीमत पर सीएनजी-पीएनजी मिलेगी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने बताया कि हाल में आंध्र प्रदेश सरकर ने नेचुरल गैस की कीमतों पर वैट की वर्तमान दर 24.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गेल इंडिया ने भी वाणिज्यकर विभाग से अनुरोध किया है कि बिहार में नेचुरल गैस की कीमतों पर वैट की दर घटाकर पाँच फीसदी किया जाये।

उद्योगों को मिलेगी राहत : पटवारी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त व उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांग की है कि आंध्र प्रदेश की तरह नेचुरल गैस पर वैट की दर को बिहार में भी घटाकर 5 प्रतिशत की जाय।

महाप्रबंधक ए. के. सिन्हा ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तामिलनाडु, कर्नाटक व केरल में नेचुरल गैस पर वैट की दर 0 से छह फीसदी तक है, जिससे आंध्र प्रदेश में चल रही औद्योगिक इकाइयों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने वेट की दर जो 24.5 प्रतिशत था, उसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। **(साभार : प्रभात खबर, 2.3.2024)**

बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक-2024 विधान सभा में हुआ पारित

टैक्स का 35%, ब्याज व पेनाल्टी का 10% देकर कारोबारी विवाद से मिलेगा छुटकारा

वैट अधिनियम के तहत कर विवाद में फंसे राज्य के हजारों कारोबारियों के लिए खुशखबरी है। वह विवादित कर राशि का 35% और ब्याज व पेनल्टी की राशि का 10% देकर कर विवाद से छुटकारा पा सकते हैं। राज्य सरकार उनके लिए एक बार फिर एकमुश्त कर समाधान योजना ला रही है। विधान सभा में कर विवाद निपटारे से संबंधित बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया। चर्चा के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

राज्य में इस तरह की योजना वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में लागू की जा चुकी है। दरअसल 1 जुलाई, 2017 से राज्य में माल और सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू है।

इस समाधान योजना में 31 जनवरी 2024 तक के विवादों का निपटारा किया जा सकेगा : जीएसटी प्रणाली लागू होने के पहले के अधिनियम यथा- बिहार वैट अधिनियम, प्रवेश-कर, मनोरंजन-कर, विज्ञापन-कर, विलासिता-कर और विद्युत ड्यूटी-कर के बकाया को लेकर मामले लंबित हैं। सरकार ने व्यापार और उद्योग जगत के अनुरोध पर एक बार फिर एकमुश्त कर समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

शुरुआत में योजना छह माह तक लागू रहेगी : फिलहाल यह योजना छह माह तक लागू रहेगी, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे, तो इसे अगले छह माह के लिए और बढ़ा सकती है। समाधान योजना में ब्याज और पेनाल्टी के मामलों में 90 प्रतिशत की माफी दी गयी है। विवादित ब्याज और पेनल्टी का मात्र 10 प्रतिशत भुगतान करने पर विवाद का निपटारा हो जायेगा। वहीं, बकाया कर के मामलों में 65 प्रतिशत की माफी दी गयी है, अर्थात् बकाया कर की विवादित राशि का मात्र 35 प्रतिशत भुगतान करने पर विवाद समाप्त हो जायेगा। यदि किसी व्यवसायी द्वारा विवादित बकाया कर, ब्याज व पेनाल्टी के मद में पहले से कोई राशि जमा है, तो इसे समाधान राशि का भुगतान माना जायेगा। व्यवसायी को मात्र अंतर राशि देनी होगी।

पेट्रोल-डीजल पंप व्यवसायी को अब नहीं दाखिल करना होगा वैट रिटर्न : राज्य में अब पेट्रोल-डीजल पंप व्यवसायियों को वैट रिटर्न नहीं दाखिल करना होगा। इसके लिए बिहार वैट अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधान सभा ने बिहार वैट (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित कर दिया। विधान सभा में वैट संशोधन विधेयक पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी से डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को बाहर रखा गया है। राज्य में इनका कर प्रशासन बिहार वैट अधिनियम के द्वारा होता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एसोसिएशन की लंबे समय से मांग पर विचार करते हुये पेट्रोल-डीजल कारोबारियों को रिटर्न नहीं दाखिल करने की छूट दी है।

(साभार : प्रभात खबर, 11.03.2024)

थाना, जिला व मुख्यालय स्तर पर खुले डाटा सेंटर्स बनेंगे आधार

बिहार में होगी डिजिटल पुलिसिंग, अपराधियों की ट्रैकिंग अब आसान

स्मार्टफोन व लैपटॉप से लैस होंगे आइओ, थानों के सभी पदाधिकारियों को मिलेगी डिजिटल अनुसंधान की ट्रेनिंग

भविष्य की चुनौतियों को ध्यान रखते हुए बिहार पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग की तैयारी कर ली है. अधिसूचित आपराधिक कानूनों में अनुसंधान से लेकर ट्रायल तक में तकनीक की अनिवार्यता पर जोर है. इसको देखते हुए बिहार पुलिस थाना से लेकर जिला व राज्य मुख्यालय तक डेटा मैनेजमेंट और पुलिसकर्मियों की डिजिटल ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है. पुलिस ने अनुसंधान

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उद्योग मंत्री, बिहार से मिलकर उन्हें बधाई दी

बिहार चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल 18 मार्च 2024 को अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री नीतीश मिश्रा से उनके आवास पर मिला एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर उन्हें बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

कर्मियों को लैपटॉप और अत्याधुनिक स्मार्टफोन से लैस कर उन्हें ट्रेंड करने की योजना बनायी है. मॉडल के रूप में एक जिले से डिजिटल पुलिसिंग की शुरुआत की जा रही है. **(विस्तृत : प्रभात खबर, 4.3.2024)**

अप्रैल से फरवरी तक पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक जीएसटी संग्रह

फरवरी-2023 की तुलना में फरवरी 2024 में राजस्व वसूली हुई कम

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) धीरे-धीरे सेटल होता जा रहा है। साल दर साल बिहार के जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह अधिक हुआ है। बिहार में अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान जीएसटी संग्रह में वार्षिक 12% की वृद्धि हुई थी। इस अवधि में जीएसटी संग्रह 21319 करोड़ था, जो 2023-24 के अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के दौरान बढ़कर 24231 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इस अवधि की तुलना में रुपये के टर्म में 2912 करोड़ और प्रतिशत के टर्म में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024 में कम जीएसटी संग्रह हुआ है। फरवरी 2023 में 1499 करोड़ और फरवरी 2024 में 1491 करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ यानी एक फीसदी कम संग्रह हुआ है.

झारखंड में भी 1% कम जीएसटी संग्रह हुआ : झारखंड में भी फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024 में एक फीसदी कम जीएसटी संग्रह हुआ। झारखंड में फरवरी 2023 में 2962 करोड़ और फरवरी 2024 में 2933 करोड़ ही संग्रह हुआ है। हालांकि यूपी और बंगाल में इस अवधि में 8% अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। वहीं, अगर बात अप्रैल-2023 से फरवरी 2024 तक की करें, तो इस अवधि में झारखंड में 8%, पश्चिम बंगाल में 7% और उत्तर प्रदेश में 15% अधिक राजस्व संग्रह हुआ. **(साभार : प्रभात खबर, 04.03.2024)**

क्यूआर कोड से भारत व नेपाल के बीच लेन-देन शुरू

भारत के सहयोग से नेपाल ने भी डिजिटल लेन-देन की दुनिया में कदम रखा है। दोनों देशों के लोग अब डिजिटिल पेमेंट प्लेटफार्म पर क्यूआर कोड स्कैन कर लेन-देन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत सिटिजन बैंक इंटरनेशनल और ज्योति विकास बैंक से हुई है। भारत के फोन पे, भीम तथा यूपीआइ के माध्यम से नेपाल में क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान किया गया। अभी पांच हजार रुपये के लेनदेन के साथ सेवा शुरू की गई है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सीमा बढ़ाई जाएगी। डिजिटल पेमेंट लागू होने से दोनों देशों के नागरिकों को आसानी होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 1.03.2024)**

बिहार में पुराने वाहनों का पहला स्क्रैप सेंटर बख्तियारपुर में खुला

राज्य के पहले स्क्रैप सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। पटना से 40 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के टेक बिगहा में खुले इस सेंटर में केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण गाइडलाइन के अनुरूप गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम हो रहा है। फिलहाल यहां ज्यादातर गाड़ियां नीलामी के जरिए लायी जा रही है।

श्री निलयम प्री-कॉटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किए गए स्क्रैप सेंटर के प्रबंधक एस. के. सिंह ने बताया कि यहां गाड़ियों को स्क्रैप कराने के बाद केंद्र द्वारा वाहन मालिकों को दो प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। पहला सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट (सीओडी) और स्क्रैप होने के बाद दूसरा प्रमाण -पत्र सर्टिफिकेट ऑफ व्हेकिल स्क्रैपिंग मिलता है। इन प्रमाण-पत्रों का लाभ नई गाड़ियों की खरीदारी के समय ग्राहकों को मिलता है। स्क्रैप केंद्र पर गाड़ियों के वजन के अनुसार 25 रुपये किलो की दर से गाड़ी मालिक को दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वैगन आर, स्वीफ्ट और आई 10 जैसी गाड़ियों के स्क्रैप से वाहन मालिक को लगभग 25 हजार प्राप्त होते हैं। सर्टिफिकेट केवल उन्हीं गाड़ियों के लिए दिए जाते हैं जिसका विवरण वाहन पोर्टल पर मौजूद है।

स्क्रैप गाड़ियों पर लगी पेनाल्टी भी सौ प्रतिशत माफ : सीओडी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के दो साल के अंदर नई गाडियों की खरीदारी पर ग्राहकों को कई तरह के लाभ प्राप्त होते है। इनमें सबसे बड़ा लाभ रोड टैक्स (मोटर व्हेकिल टैक्स) में मिल रहा है। सीओडी प्रमाणपत्र को नई गाड़ियों की खरीद में जमा कराने पर रोड टैक्स का 25 प्रतिशत माफ हो जाता है। स्क्रैप केंद्र के अधिकारियों के अनुसार 15 लाख रुपये की गाडियों पर लगभग 50 हजार तक की छूट मिल रही है।

जागरूकता का है अभाव : गाड़ियों की स्क्रैप नीति को लेकर वाहन मालिकों में जागरूकता का अभाव है। इसके कारण पटना और आसपास स्थित अवैध स्क्रैप सेंटरों में गाडियों की कटिंग भी हो रही है। इन अवैध केंद्रों पर बिकने वाली गाड़ियों की मरम्मत कर दुरुपयोग की भी आशंका बनी रहती है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 01.03.2024)

क्या आपको भी कोई फर्जी कॉल आई? 'चक्षु' पर शिकायत करें.... चंद घंटों में ही होगा एक्शन

अगर आपको कभी भी सेक्सटॉर्शन, धमकी, ऑनलाइन जॉब, या केवाईसी आदि का झांसा देकर कोई कॉल, एसएमएस या वॉट्सएप आया है, तो यह खबर जरूर पढ़ें।

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी

बिहार चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल 18 मार्च 2024 को अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में माननीय सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार डॉ. प्रेम कुमार से मिला एवं उन्हें पुष्प- गुच्छ भेंटकर शुभकामनाएं दी।

प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता सम्मिलित थे।

ऐसे साइबर अपराधों की शिकायत के लिए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर दो प्लेटफॉर्म (चक्षु और डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी) लॉन्च किए।

अगर कोई साइबर अपराध हो गया है तो उसे डीआईपी पर रिपोर्ट करें। अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है जिससे साइबर फ्रॉड या अपराध होने की आशंका है तो चक्षु पर रिपोर्ट करें।

संचार साथी : घर बैठे ऐसे कर सकते हैं रिपोर्ट...

स्टेप बाय स्टेप जानिए पूरी प्रक्रिया

1. sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलें।
2. सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक करें।
3. पहले बॉक्स में रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन (चक्षु) दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
4. चक्षु नाम से विंडो ओपन होगी, इसमें नीचे कंटीन्यू फॉर रिपोर्टिंग पर क्लिक कर दें।
5. पहला सवाल दिखेगा कि आपसे कैसे संपर्क किया गया ? तीन ऑप्शन होंगे- एसएमएस, कॉल, वॉट्सएप । इसमें से एक सिलेक्ट करें।
6. दूसरे सवाल में पूछा जाएगा कि किस संबंध में बातचीत हुई? इसमें सेक्सटॉर्शन, केवाईसी जैसे कई ऑप्शन दिखेंगे, इनमें से एक सिलेक्ट करें।
7. फिर स्क्रीन शॉट अटैच करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं।
8. जिस दिन और समय पर कॉल, मैसेज या वॉट्सएप आया, उसे दर्ज कर दें।
9. अधिकतम 500 शब्दों में शिकायत लिख दें।
10. इसके बाद नाम और नंबर दर्ज करें।
11. मोबाइल नंबर वेरिफाई करने के लिए दिया गया कैप्चा टाइप करें और वेरिफाई मोबाइल वाया ओटीपी पर क्लिक कर दें। शिकायत दर्ज हो जाएगी।

ऐसे काम करेगा यह प्लेटफॉर्म : जहां भी नंबर एक्टिव होगा, वहां की लोकल पुलिस को जानकारी चली जाएगी। नंबर के मालिक से कहा जाएगा कि 2 दिन में दोबारा केवाईसी कराएं। आउटगोइंग तत्काल बंद कर दी जाएगी। केवाईसी न कराने पर एजेंसियां एक्शन लेना शुरू कर देंगी। इंटरनेट आधारित कॉल्स हैं तो यह एप आईपी एड्रेस मैप करेगा। जहां से लिंक, मैसेज या कॉल बल्क में किए जा रहे हैं, उसे ट्रेस करना आसान हो जाएगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 5.3.2024)

जमीन की जमाबंदी करने को हर मंगल, बुध और गुरुवार को लगेंगे कैंप

राज्य में जमीन की बिक्री करने के लिए जमाबंदी अनिवार्य कर दी गई है। यानी, जिस व्यक्ति के नाम से जमीन होगी, वही बेच सकेगा। इस नियम के आने के बाद पूर्वजों के नाम से संयुक्त परिवारों की जमीन पर अलग-अलग दखल-कब्जा होने के बावजूद जमाबंदी नहीं होने से बिक्री नहीं हो रही है। शादी-विवाह और इलाज के लिए लोग अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद निबंधन विभाग के प्रस्ताव पर भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को शिविर लगाकर जमाबंदी कायम कराने का आदेश दिया है।

सभी हलकों में सार्वजनिक स्थलों पर होगा आयोजन : प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को पंचायत सरकार भवन, ग्राम कचहरी भवन, सामुदायिक भवन और अन्य चिह्नित सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगेंगे। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने सभी सीओ को सभी हलकों के सार्वजनिक स्थानों को चिह्नित कर कैंप लगाने का निर्देश दिया है। इसमें वंशावली और बंटवारा के आधार पर नामांतरण से संबंधित आवेदन, परिमार्जन से संबंधित आवेदन लिया जाएगा। किसी हलका कर्मचारी पर तीन से अधिक प्रभार होने पर शुक्रवार को भी कैंप लगेगा।

अंचल कार्यालय में भी खुलेगा अलग काउंटर : डीएम ने सीओ को अंचल कार्यालय में अलग काउंटर खोलने का निर्देश दिया है। शिविर के अलावा लोग यहां भी वंशावली और बंटवारा के आधार पर नामांतरण और परिमार्जन से संबंधित आवेदन जमा कर सकेंगे।

पारिवारिक बंटवारा के आधार पर जमाबंदी : तय नियम के अनुसार पंचायत सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच वंशावली जारी करेंगे। इसके आधार पर संयुक्त जमाबंदी में अलग-अलग हिस्सेदारों के नाम से नामांतरण के लिए बंटवारा पत्र देंगे। इसके आलोक में अलग-अलग जमाबंदी कायम होगी।

दाखिल-खारिज और नामांतरण में अंतर : पुरानी जमाबंदी से अलग -अलग हिस्सेदारों के नाम से नई जमाबंदी कायम करने वाले आवेदन को नामांतरण कहा जाता है। जमीन की बिक्री होने पर खरीदार के नाम से दाखिल-खारिज किया जाता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 05.03.2024)

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय नगर विकास एवं आवास तथा विधि मंत्री, बिहार से मिलकर उन्हें बधाई दी

बिहार चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल 18 मार्च 2024 को अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में माननीय नगर विकास एवं आवास तथा विधि मंत्री, बिहार श्री नितीन नबीन से मिला एवं उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

दोनों जिलों से जुड़े देव के जंगली इलाके में टिन और टंगस्टन खनिज की होगी खोज, केंद्रीय खनिज मंत्रालय ने इन खनिजों के पाए जाने की पुष्टि की

गया-औरंगाबाद जिले में दो खनिज ब्लॉक का होगा विकास

औरंगाबाद जिले में देव से दक्षिण मौजूद जंगली इलाके में टिन और टंगस्टन के साथ आरईई (रेयर अर्थ इलेमेंट्स) खनिज की खोज की जाएगी। देव के इस जंगली इलाके का एक हिस्सा गया जिले में भी पड़ता है। 550 वर्ग किमी के इस बड़े भू-भाग में दो प्रमुख खनिजों टीन और टंगस्टन की खोज की जाएगी।

केंद्रीय खनिज मंत्रालय ने इस क्षेत्र में इन पदार्थों के पाए जाने की पुष्टि करते हुए इसका अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक बिहार को आवंटित कर दिया है। इस बड़े हिस्से में खनिज का खनन शुरू करने से पहले एक कंपनी का चयन किया जाएगा, जो इस बड़े हिस्से में उस खास स्थान को चिह्नित करेगी, जहां इनका बड़ा भंडार है। साथ ही उनकी मात्रा भी पता करेगी। कंपनी का चयन करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द ही खान एवं भूतत्व विभाग शुरू करेगा। इसकी प्रक्रिया दो से तीन महीने में पूरी हो जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 01.03.2024)**

बिहटा और मुजफ्फरपुर होजरी उत्पादन के नये केंद्र बनेंगे

बिहटा के सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 8 मार्च, 2024 को उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक और होजरी निर्माता कंपनी टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय जैन ने मेड इन बिहार लोगो को लॉन्च किया।

अपर मुख्य सचिव पौण्डरीक ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़े नए उद्यमियों की मदद के लिए बड़ी कंपनियों के साथ तालमेल को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में होजरी का उत्पादन कोलकाता और तिरुपुर में मुख्य रूप से होता है, लेकिन बिहटा और मुजफ्फरपुर होजरी उत्पादन के नए केंद्र बने, इसके लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां के 30 से 40% लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर भटक रहे हैं। जिसको रोकने के लिए उद्योग लगाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दे रही है। बिहार में 13 करोड़ जनता के लिए सामान बिहार में निर्मित होगा। इसके तहत पहले आठ लाभुकों को टीटी लिमिटेड के साथ जोड़ा गया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 09.03.2024)**

कंपनियां ट्रेड सीक्रेट के संरक्षण के लिए कानूनी कवच मांगती रही हैं

पहली बार बनेगा ट्रेड सीक्रेट एक्ट, गोपनीय फॉर्मूला अब नहीं बताना होगा ; विधि आयोग ने सौंपा मसौदा

1977 में जब मोरारजी देसाई सरकार ने अमेरिका की कोका कोला कंपनी से फॉर्मूला उजागर करने को कहा तो वह कारोबार समेट कर लौट गई थी। ट्रेड सीक्रेट न पूछे जाने का भरोसा मिलने पर कंपनी 1993 में लौटी। तभी से भारत के साथ कारोबार करते समय विदेशी कंपनियां अपने ट्रेड सीक्रेट और विभिन्न गोपनीय सूचनाओं के संरक्षण के लिए कानूनी कवच मांगती रही थीं। यह आखिरकार उन्हें मिलने जा रहा है। विधि आयोग ने केंद्र सरकार को 289वीं रिपोर्ट का मसौदा सौंप दिया है। इसमें ट्रेड सीक्रेट एक्ट और आर्थिक गुप्तचरी को लेकर अलग कानून का उल्लेख है।

आयोग ने व्यापक विचार-विमर्श कर जाना कि सीक्रेट उजागर करने के लिए किन मामलों को अपवाद माना जाना चाहिए। देश में अब तक ऐसा कानून नहीं है, जो किसी वस्तु को बनाने का राज सुरक्षित रखता हो । बौद्धिक संपदा कानून और कॉपीराइट एक्ट इस जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। भारत डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुका है। इसके तहत ट्रेड सीक्रेट को संरक्षण देना लाजिमी है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 10.3.2024)**

बिजली कंपनियों को 30 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी का करना होगा इस्तेमाल

सूबे की बिजली आपूर्ति कंपनियों को 2024-25 में खर्च होने वाली कुल बिजली में 30% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। यह बिजली सोलर, हाइड्रो, विंड आदि गैर पारंपरिक माध्यमों द्वारा उत्पादित होगी।

विद्युत विनियामक आयोग ने रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन (आरपीओ) के तहत लक्ष्य निर्धारित करते हुए आपूर्ति कंपनियों को इसका पालन करने का निर्देश दिया है। लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाली आपूर्ति कंपनी पर आरपीओ नियमों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

वर्तमान में बिजली आपूर्ति की कुल अनुबंधित क्षमता 9002 मेगावाट में 2486 मेगावाट (27.6 फीसदी) बिजली गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त होती है. 2024-25 में 1540 मेगावाट अतिरिक्त बिजली-गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त कर इस लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी. आयोग ने 30% रिन्युएबल एनर्जी में 2.46 फीसदी विंड, 1.08 फीसदी हाइड्रो और शेष 26.37 फीसदी सोलर प्राप्त करने का लक्ष्य दिया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 05.03.2024)**

अब गोदाम में रखे उत्पादों पर लोन ले सकेंगे किसान

किसान अब पंजीकृत गोदामों में रखे अपने उत्पादों पर लोन ले सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ऐसे लोन की सुविधा देने वाला डिजिटल प्लेटफार्म लांच किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल प्लेटफार्म ई-किसान उपज निधि लांच करते समय केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथारिटी (डब्ल्यूडीआरए) के पास पंजीकृत गोदामों में रखे उत्पादों पर किसान को बैंकों से कर्ज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे सात प्रतिशत की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डब्ल्यूडीआरए की ओर से गोदाम मालिकों से ली जाने वाली सुरक्षा राशि को भी स्टाक मूल्य का तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.3.2024)**

चैम्बर के सदस्यों ने एक दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली की बधाई दी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 22 मार्च 2024 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें एक दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली की बधाई दी गई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने कहा है कि होली आपसी प्रेम एवं एकता का प्रतीक है। होली हमें सभी मतभेदों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने की प्रेरणा देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

श्री नन्द किशोर यादव, माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा का स्वागत करते चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, समारोह के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन, श्री आशीष प्रसाद एवं अन्य।

समारोह में पधारे माननीय सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार का स्वागत करते उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, होली मिलन समारोह समिति के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन, सह-संयोजक श्री पवन भगत, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद एवं श्री अजय गुप्ता।

समारोह में पधारे माननीय नगर विकास, आवास एवं विधि मंत्री श्री नीतीन नवीन। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

माननीय बिहार विधान पार्षद श्री ललन सराफ का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री अमर अग्रवाल एवं श्री संतोष कुमार अग्रवाल।

सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद का स्वागत करते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री ऋतुराज सिन्हा का स्वागत करते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

समारोह के सेल्की प्वाइंट पर माननीय उप महापौर श्रीमती रश्मि चन्द्रवंशी का स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्त एवं श्री आशीष प्रसाद।

समारोह में उपस्थित माननीय सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, माननीय नगर विकास एवं आवास तथा विधि मंत्री श्री नीतीन नवीन। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

समारोह में उपस्थित डॉ. प्रेम कुमार, माननीय सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं मा.ज.पा. के राष्ट्रीय सचिव श्री ऋतुराज सिन्हा। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी का स्वागत करते होली मिलन समारोह आयोजन समिति के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य

सेल्फी प्वाइंट पर उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

सेल्फी प्वाईट पर चैम्बर उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

सेल्फी प्वाईंट पर उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, होली मिलन समारोह आयोजन समिति के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन, सह संयोजक श्री पवन भगत, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ एवं श्री आशीष प्रसाद।

राधा-कृष्ण के नृत्य में झूमते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

समारोह में कलाकार कृष्ण के साथ-साथ झूमते-गाते चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण।

समारोह में कलाकार कृष्ण के साथ-साथ झूमते-गाते चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण।

समारोह में राधा-कृष्ण के नृत्य का आनन्द उठाते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

कलाकारों द्वारा होली गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति।

समारोह में होली गीत पर नृत्य करती नृत्यांगणा

समारोह में ठंढई एवं विविध व्यंजनों का रसास्वादन करते अतिथिगण एवं सदस्यगण।

एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से होली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी मेल-जोल को बढ़ावा दिया जाता है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पटवारी ने कहा कि चूंकि रंग एवं अबीर में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग होने लगा है, जो शरीर की त्वचा को तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है और इससे जल की भी बर्बादी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ने पर्यावरण अनुकूल रंग-अबीर रहित फूलों की होली का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आगन्तुकों के लिए होली के पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उनके मनोरंजन हेतु साईं म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने होली के पारंपरिक गीतों एवं नृत्यों से सभी श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया।

श्री पटवारी ने कहा कि चैम्बर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में चैम्बर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ राज्य के सभी तबके के गणमान्य महानुभाव सपरिवार सम्मिलित होकर एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी।

इस समारोह में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, श्री नन्द किशोर यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री नीतीन नवीन, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, विधान पार्षद श्री ललन सराफ, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, उप महापौर श्रीमति रश्मि चंद्रवंशी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री ऋतुराज सिन्हा के साथ-साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बैंक के अधिकारी, अधिवक्ता एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने पधारकर चैम्बर परिवार को गौरवान्वित किया।

समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कार्यक्रम के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन, सह-संयोजक श्री पवन भगत, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री राज बाबू गुप्ता, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम डोलिया, श्री शशि गोयल, श्री राकेश कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री राजेश जैन, श्री अशोक कुमार के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यापारी सपरिवार समारोह में सम्मिलित हुए। होली मिलन समारोह सदस्यों के स्मृति में काफी दिनों तक बना रहेगा।

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने नव-नियुक्त मुख्य सचिव, बिहार से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 5 मार्च 2024 को नवनियुक्त मुख्य सचिव, बिहार श्री बृजेश मेहरोत्रा, भा.प्र.से. को उनके पदभार ग्रहण करने पर पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनंदन किया एवं बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सम्मिलित थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने प्रीपेड ताम्र टिकट के 250 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष आवरण का विमोचन किया

प्रीपेड कॉपर (ताम्र) टिकट जारी होने के 250 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 31 मार्च 2024 को पटना जी.पी.ओ. में विशेष आवरण का विमोचन चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में किया। इस समारोह में चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन भी शामिल थे।

विशेष अनावरण समारोह में न्यायमूर्ति राकेश कुमार, पद्मश्री बिमल कुमार जैन, शिक्षाविद खान सर, कुलपति डॉ. रास बिहारी प्रसाद सिंह, बिहार सर्किल के मुख्य डाक माहाध्यक्ष श्री अनिल कुमार, डाक निदेशक श्री मोहन कुमार नाथ एवं चैम्बर सदस्य तथा फिलाटेलिस्ट श्री प्रदीप जैन भी मंचासीन थे।

चैम्बर अध्यक्ष बिहार विद्युत् विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के नव-पदस्थापित अध्यक्ष से मिले एवं शुभकामनाएं दीं

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने वरीय सदस्य श्री संजय कुमार भरतिया के साथ 11 मार्च 2024 को बिहार विद्युत् विनियामक आयोग (BERC) के नव-पदस्थापित अध्यक्ष श्री आमीर सुबहानी, भा.प्र.से. से उनके कार्यालय कक्ष में औपचारिक भेंट की और नव-पदस्थापना की शुभकामनाएं दी।

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव से मिलकर किया विमर्श

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल 5 मार्च 2024 को चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में डॉ. प्रतिमा, भा.प्र.से., वाणिज्य-कर आयुक्त-सह सचिव से उनके कार्यालय कक्ष में मिला एवं राज्य में PNG/CNG गैस पर लगने वाले VAT की दर को आंध्रप्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के भांति कम किये जाने तथा कोयला / फर्नेश आयल से चलने वाले औद्योगिक ईकाइयों के पीएनजी में परिवर्तित होने के कारण होनेवाली कठिनाइयों के संबंध में उनसे विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ एवं अभिजित बैद सम्मिलित थे।

सिक्स लेन पुल. दक्षिण व उत्तर बिहार को मिलेगी नयी कनेक्टिविटी

पीएम ने जेपी सेतु की बगल में पुल की रखी नींव, चार साल में होगा तैयार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 6.3.2024 को पटना में गंगा नदी पर दीघा-सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर छह लेन के पुल का शिलान्यास किया। यह पुल एनएच -139 डब्ल्यू पटना से बेतिया सड़क सहित बुद्ध सर्किट का हिस्सा है। करीब 3,064.45 करोड़ रुपये से बनने वाले करीब 4.56 किमी लंबे पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्तमान जेपी सेतु के समानांतर इससे 180 मीटर पश्चिम में नया एक्सट्रा डोज केबल सिक्स लेन पुल का निर्माण करने के लिए एसपी सिंगला कंपनी को जिम्मेदारी दी गयी है। माना जा रहा है कि अगले माह अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। साथ ही 2027 में इस पुल से आवागमन शुरू होने की संभावना है।

गंगा पर बन रहे पाँच पुल : प्रधानमंत्री ने इस पुल का शिलान्यास करते हुए कहा कि गंगा नदी पर छह लेन के केबल आधारित ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। बिहार में 22 हजार करोड़ रुपये से एक दर्जन से अधिक पुल पर काम चल रहा है, जिनमें से पाँच पुल तो गंगा नदी पर बन रहे हैं। ये पुल, ये चौड़े रास्ते ही तो विकास का मार्ग बनाते हैं, उद्योगों को लाते हैं।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 7.3.2024)

बिहार-झारखण्ड के बीच रेल संपर्क आसान करेगा बटेश्वरनाथ रेल पुल

भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला-कटरिया रेल पुल प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने वाला है। इससे बिहार-झारखण्ड के निवासियों का आना-जाना आसान हो जाएगा। इस योजना के तहत भागलपुर की तरफ बटेश्वरनाथ स्थान से गंगा के दूसरी ओर नवगछिया के कटरिया तक नई रेल लाइन बनेगी। इससे गंगा के दोनों किनारे जुड़ जाएँगे। बिहार के सीमांचल के जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज से आगे राँची तक की रेल से सफर करना आसान हो जाएगा।

गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर इस 23 किलोमीटर ऐतिहासिक बाइपास लाइन के लिए रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सहमति दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि कैबिनेट के स्तर पर इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द काम आगे बढ़ेगा। डेढ़ सौ किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन देवघर से हंसडिहा-गोड्डा-पीरपैंती-विक्रमशिला-बटेश्वर स्थान से नौगछिया में मिलेगी। इस लाइन का 127 किलोमीटर का काम हो चुका है। बटेश्वर स्थान के पास गंगा के दोनों छोरों को रेल पुल के जरिए जुड़ने से रेलवे लाइन का 23 किलोमीटर और विस्तार हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय ने बटेश्वर स्थान से कटारिया रेल पुल के सर्वे का कार्य पिछले वर्ष ही पूरा कर लिया था। देवघर से हंसडिहा, गोड्डा एवं पीरपैंती होते हुए यह गंगा पुल नौगछिया से जुड़ेगा। यह लाइन हावड़ा-पटना, देवघर-दुमका, भागलपुर रामपुरहाट, जमालपुर हावड़ा मालदा एवं पटना बरौनी और कटिहार सहित पाँच रेल लाइन के बाइपास का भी काम करेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.3.2024)

बिहटा में फल-सब्जियों की होगी पैकिंग, विदेशों तक भेजे जायेंगे

मुख्यमंत्री ने 59 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा में इ-रेडिएशन सेंटर एवं एक्सपोर्ट पैक हाउस लोकार्पित किया। यहां कृषि उत्पादों के रेडिएशन एवं पैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक्सपोर्ट पैक हाउस एक खास अत्याधुनिक सेंटर होता है जिसके जरिए खाद्य पदार्थ खासतौर पर हरे उत्पाद फल-सब्जियों की हानिमुक्त पैकिंग की जाती है। यहां से इसे देश-विदेश तक भेजा जायेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण एवं भागलपुर में 24 लाख लर्गफुट के प्लग एंड प्ले शेड का भी सीएम ने उद्घाटन किया। 106 करोड़ की लागत से फतुहा, पूर्णिया तथा बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, बिटुमिनस रोड व स्ट्रीट लाइट संबंधी योजना का शिलान्यास किया। 21 करोड़ की लागत से पटना में गांधी मैदान के पास उद्योग भवन व फ्रेजर रोड के बीएसएफसी बिल्डिंग में नये स्टार्टअप बिजनेस सेंटर संबंधी योजनाओं के साथ-साथ गोरौल में फ्लेक्सिबल पेमेंट योजना भी शामिल हैं।

सीएम ने पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण व भागलपुर में प्लग एंड प्ले शेड्स का भी किया उद्घाटन

सीएम ने 9.40 करोड़ की लागत से नालंदा, भागलपुर और गोपालगंज में जिला उद्योग केंद्र के नये भवन तथा बक्सर जिले में बियाडा कार्यालय के भवन का भी शिलान्यास किया। साथ ही 36 करोड़ 97 लाख की रुपये की लागत से भागलपुर जिले में सीपेट बिल्डिंग तथा हाजीपुर जिले में सीपेट ब्वायज हॉस्टल का निर्माण कार्य एवं 31 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से मोतीपुर एवं पानापुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क एवं पुल का निर्माण कार्य शामिल हैं. इसके

चैम्बर अध्यक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के स्टील उद्योग से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 6 मार्च 2024 को एक बैठक का आयोजन श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, स्टील मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में होटल पाटलिपुत्र कॉन्टिनेंटल, पटना में हुआ।

बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी सम्मिलित हुए।

अलावा सात करोड़ की लागत से दिनारा में टूल एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व हॉस्टल निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया।

यह रहे मौजूद : कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी, पर्यटन मंत्री डॉ प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, विकास आयुक्त चौतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार जुड़े रहे। **(साभार : प्रभात खबर, 07.03.2024)**

ईंट भट्टों को खुदाई में छूट संबंधी अधिसूचना हाईकोर्ट ने खारिज की

हाईकोर्ट ने राज्य में बगैर पर्यावरण क्लीयरेंस के ईंट भट्ठों को डेढ़ मीटर तक मिट्टी की खुदाई करने की अनुमति देने के मामले पर सुनवाई करते हुए संबंधित दोनों अधिसूचना को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अभय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका के जरिए उस अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया गया था, जिसके जरिए ईंट भट्ठों के लिए खास मौसम में, किसी खास जमीन की खुदाई कर मिट्टी निकालने की अनुमति राज्य सरकार के माइंस व जियोलॉजी विभाग के अवर सचिव द्वारा नियम में संशोधन करके 14 सितंबर, 2020 को दी गई है। याचिका में बिहार स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, बिहार के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी उस अधिसूचना को भी रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके जरिए ईंट भट्ठों को डेढ़ मीटर तक जमीन की खुदाई कर मिट्टी निकालने को माइनिंग की परिभाषा से छूट दी गई।

(साभार : दैनिक भास्कर, 08.03.2024)

किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट मिलने लगेगी बिजली

एक अप्रैल से 15 पैसे सस्ती मिलेगी बिजली

राज्य के दो करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी

एक अप्रैल से बिजली दर में कमी आ जाएगी। से बिजली दर में कमी आ जाएगी। राज्य के दो करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिहार सरकार बिजली कंपनी को 15,343 करोड़ रुपये अनुदान देकर विद्युत दर में कमी लाई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के पक्ष सुनने के बाद ऊर्जा शुल्क में 15 पैसे की कमी कर दी है। फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीटर से कनेक्शन लेने वाले किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पहले 70 पैसे प्रति यूनिट लगती थी।

किसानों को फसल चक्र के अनुसार बिल साल में चार बार मिलेंगे, फिक्स चार्ज नहीं लगेगा। बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रति एचपी 85 रुपये की दर से शुल्क भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष से विद्युत टैरिफ स्लैब दो भाग में बांटा गया है। शून्य से 100 यूनिट तक दर कम है तथा उससे अधिक बिजली उपभोग करने पर ज्यादा शुल्क लगते उपभोग करने पर ज्यादा शुल्क लगते हैं। घरेलू, उद्योग से जुड़े उपभोक्ता और किसानों को राहत मिलेगी। विद्युत कंपनी एक अप्रैल से नई दर से बिजली शुल्क पर बिजली बिल जारी करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे से संबंधित कारोबार करने वालों को घरेलू विद्युत दर देनी पड़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्युत शुल्क

शहरी उपभोक्ता घरेलू

यूनिट	फिक्स चार्ज	नई दर	2023-24 (अनुदान के बाद)	2024-25
100 से नीचे	80 रुपये	7.42 रुपये	4.27 रुपये	4.12 रुपये
100 से ऊपर	80 रुपये	8.95 रुपये	5.67 रुपये	4.52 रुपये

ग्रामीण उपभोक्ता घरेलू

यूनिट	फिक्स चार्ज	नई दर	2023-24 (अनुदान के बाद)	2024-25
प्रथम 50 यूनिट	40 रुपये	7.42 रुपये	2.60 रुपये	2.45 रुपये
50 यूनिट से +	40 रुपये	7.96 रुपये	3.00 रुपये	2.85 रुपये

शहरी उपभोक्ता कामर्शियल

यूनिट	फिक्स चार्ज	नई दर	2023-24 (अनुदान के बाद)	2024-25
0.5 किलोवाट	200 रुपये	7.73 रुपये	5.82 रुपये	5.67 रुपये
100 से नीचे	300 रुपये	7.73 रुपये	5.82 रुपये	5.67 रुपये
100 से ऊपर	300 रुपये	8.93 रुपये	6.59 रुपये	6.44 रुपये

ग्रामीण उपभोक्ता कामर्शियल

यूनिट	फिक्स चार्ज	नई दर	2023-24 (अनुदान के बाद)	2024-25
100 से नीचे	60 रुपये	7.79 रुपये	3.50 रुपये	3.35 रुपये
100 से ऊपर	60 रुपये	8.21 रुपये	4.36 रुपये	4.21 रुपये

(Source: Inext,29.3.2024)

चैम्बर अध्यक्ष ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) की ओर से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव का उद्घाटन किया

मानक महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, BIS के अधिकारीगण एवं अन्य।

महोत्सव में उपस्थित उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

महोत्सव के दौरान चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को अंगवस्त्र, पौधा एवं मेमोन्टो भेंटकर सम्मानित करते बीआईएस के अधिकारी।

Bureau of Indian Standard (BIS) की ओर से दिनांक 15 मार्च 2024 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन होटल विजया तेज क्लार्क्स इन, पटना में किया गया।

इस कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित हुए। मानक महोत्सव का चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया एवं कार्यक्रम को संबोधित भी किया।

मानक महोत्सव कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को अंगवस्त्र, पौधा एवं मेमेंटो भेंटकर सम्मानित किया गया।

उपभोक्ता सस्ते में करा सकेंगे घरेलू उत्पादों की मरम्मत

अब कार से लेकर मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज जैसी घरेलू वस्तुओं के खराब होने पर उसकी मरम्मत सस्ते में करा सकेंगे। हाल ही में सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क लेकर आई है और इस फ्रेमवर्क के तहत चार सेक्टर से जुड़ी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को राइट टू रिपेयर पोर्टल पर अपने उत्पाद और उसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की विस्तृत जानकारी के साथ उनके रिपेयर की सुविधा के बारे में बताने के लिए कहा है। इन चार सेक्टर में फार्मिंग उपकरण, मोबाइल-इलेक्ट्रानिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एवं आटोमोबाइल उपकरण शामिल हैं।

राइट टू रिपेयर पोर्टल पर देनी होगी अधिकृत सर्विस सेंटर की जानकारी : राइट टू रिपेयर पोर्टल पर कंपनी के कस्टमर केयर के साथ उत्पाद में लगे पार्ट्स व उनकी कीमत जैसी चीजों की भी जानकारी होगी। इस फ्रेमवर्क से उपभोक्ता को बेचे जाने वाले सामान को लेकर पारदर्शिता भी आएगी। राइट टू रिपेयर पोर्टल पर कंपनी अपने अधिकृत सर्विस सेंटर के साथ थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर की भी जानकारी देंगी।

कंपनी को बताना होगा कि वाटर फिल्टर के कैंडल कब तक चलेंगे : सभी आरओ व वाटर फिल्टर निर्माता कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने फिल्टर पर विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उपभोक्ताओं को कैंडल के लाइफ के बारे में विस्तृत जानकारी दे। मंत्रालय ने यह महसूस किया कि कैंडल की लाइफ को लेकर वाटर फिल्टर निर्माता कंपनियाँ कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देती हैं। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 28.3.2024)**

पटना एयरपोर्ट पर अब एम्बुलिफ्ट की सुविधा

पटना एयरपोर्ट से सफर करने वाले दिव्यांग, बीमार और बुजुर्ग लोगों को फ्लाइट पर चढ़ने में होने वाली परेशानियाँ अब नहीं होंगी। वे मात्र सौ रुपये का भुगतान कर एम्बुलिफ्ट के जरिये विमान पर चढ़ सकेंगे। वैसे, यह व्यवस्था वर्ष 2022 में ही शुरू होनी थी। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सुगम भारत अभियान के तहत दिनांक 26 मार्च, 2024 से पटना एयरपोर्ट पर लागू किया।

वैसे यात्री जो व्हीलचेयर या स्ट्रेचर से पटना हवाईअड्डे पर फ्लाइट लेने आते हैं, उन्हें एम्बुलिफ्ट सुविधा के लिए सौ रुपये का टोकन लेना होगा। इच्छुक यात्री विमानन कंपनियों से संपर्क कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा उन हवाईअड्डों पर दी जा रही है, जहाँ एयरोब्रिज नहीं हैं। गौर हो कि पहले मैनुअल तरीके से उन्हें विमान पर चढ़ाया और उतारा जाता था। इससे अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती थी। **(साभार : दैनिक जागरण, 28.3.2024)**

चैम्बर उपाध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक पर्षद (BOARD OF DIRECTORS) की बैठक में शमिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक पर्षद (BOARD OF DIRECTORS) की बैठक 14 मार्च 2024 को श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विमागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर शामिल हुए।

चैम्बर उपाध्यक्ष राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट (BSFT) के न्यासी पर्षद की बैठक में सम्मिलित हुए

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (State Investment Promotion Board) की 54 वीं एवं बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट (Bihar start up Fund Trust) के न्यासी पर्षद की बैठक दिनांक 14 मार्च 2024 को श्री चैतन्य प्रसाद भा.प्र.से., विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

चैम्बर उपाध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक पर्षद (BOARD OF DIRECTORS) की बैठक में सम्मिलित हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक परिषद (Board of Directors) की बैठक दिनांक 16 मार्च 2024 को श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में, विभागीय सभा कक्ष में हुई। उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

विभागों का रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर एकाउंट खोलकर इंट्रीगेट किया जायेगा

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राशि अब 'ई-कुबेर' से मिलेगी

केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की राशि किसी अन्य एकाउंट में पार्क नहीं हो इसके लिए केद्र सरकार लगातार नये-नये तरीके अपना रही है। फिलहाल सीएसएस की राशि सिंगल नोडल एकाउंट (एसएनए) के माध्यम से जारी की जाती है, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया जा रहा है।

नयी व्यवस्था एसएनए स्पर्श (शीघ्र ट्रांसफर एकीकृत प्रणाली) 2024-25 से लागू करने योजना है। इसके लिए वित्त विभाग में तैयारी चल रही है। केन्द्रांश की राशि रिजर्व बैंक के इ-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी की जायेगी। इसके लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों को रिजर्व बैंक के इ-कुबेर प्लेटफॉर्म पर एकाउंट खोलकर इंट्रीगेट किया जायेगा। उसके बाद पीएफएमएस के तहत सभी योजनाओं को एसएनए स्पर्श पर ऑनबोर्ड किया जायेगा।

शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पशु एवं मत्स्य, समाज कल्याण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की केन्द्र प्रायोजित योजना से की जायेगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 29.3.2024)**

बैंक नहीं कर पाएँगे कार्ड कंपनियों से डील, ग्राहकों की चलेगी मर्जी

सितम्बर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड नेटवर्क चुनने की आजादी

अब लोगों को कार्ड के लिए मनचाहा नेटवर्क चुनने की आजादी होगी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए एक से ज्यादा नेटवर्क का विकल्प देंगे। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी (गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों) से कहा है कि वे वीजा जैसे कार्ड नेटवर्क्स के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करना बंद करें।

जारी सर्कुलर में आरबीआई ने कहा, 'कार्ड नेटवर्क और बैंकों के बीच कुछ व्यवस्थाएँ ग्राहकों के अनूकूल नहीं हैं। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई करार नहीं करेंगे, जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।' आरबीआई ने कहा कि मौजूदा कार्डधारकों को अगले रिन्युअल के समय नेटवर्क चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। ये निर्देश 6 सितम्बर 2024 से लागू होंगे। इस समय देश में पाँच कार्ड नेटवर्क हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रूपे और वीजा वर्ल्डवाइड इनमें शामिल हैं।

बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि जनवरी तक 10 लाख से ज्यादा कार्ड जारी करने वाले 13 कार्ड बैंक थे। इन पर ये निर्देश लागू होंगे। 22 बैंक के 10 लाख से कम कर्ड हैं। लेकिन 13 बैंकों की कुल एक्टिव कार्ड में 92% हिस्सेदारी है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 7.3.2024)**

इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में ही जारी की जाएँगी इंश्योरेंस पॉलिसी

एक अप्रैल से ई-बीमा खाता अनिवार्य होगा

इरडा ने बीमा पॉलिसी को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एक अप्रैल से अब सभी तरह की बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी होंगी। इसके लिए ई-इंश्योरेंस खाता मिलेगा, जिसमें सभी बीमा पॉलिसी डिजिटल प्रारूप में रखी जा सकेंगी। इससे कागजी बीमा पॉलिसी रखने से मुक्ति मिल जाएगी।

यह होंगे फायदे : 1. एक स्थान पर ही सभी बीमा पॉलिसी देख सकेंगे, डाउनलोड कर पाएँगे 2. कागजी दस्तावेजों के डिजिटल प्रारूप के खोने का जोखिम कम होगा 3. ई-बीमा खाते में एक साथ सभी बीमा पॉलिसी को अपडेट कर पाएंगे 4. पॉलिसी विवरण और नवीनीकरण तिथियों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे

ई-बीमा खाता खुलेगा : इसके तहत ग्राहक का ई-बीमा खाता होगा। यह खाता एनक्रिप्टेड होगा यानी केवल बीमाधारक ही इसका इस्तेमाल कर पाएगा। किसी तीसरे पक्ष की पहुँच इस तक नहीं होगी। ग्राहक को सभी पॉलिसी इस ई-खाते से जोड़नी होंगी। लिंक करने के बाद पॉलिसीधारक अपने पॉलिसी विवरण और नवीनीकरण की तिथि को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा किसी तरह की ऑनलाइन धोखाघड़ी से भी बचाव होगा।

पॉलिसी खोने का जोखिम खत्म होगा : विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पॉलिसी धारकों को काफी फायदा पहुँचेगा। यह पहल न केवल सुविधा प्रदान करती है, बल्कि पॉलिसीधारक पोर्टफोलियो की सुरक्षा और प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। पॉलिसी होल्डर को कागजी दस्तावेज खोने, फटने का डर रहता है लेकिन अब यह जोखिम नहीं होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.3.2024)

78 पैसेंजर ट्रेनों से स्पेशल का दर्जा हटा, अब न्यूनतम किराया 10 रुपए ही लगेगा

अब पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने पर न्यूनतम किराया 10 रुपए लगेगा। कोरोना काल से पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेलमंडल में पैसेंजर ट्रेनों के नंबर के आगे जीरो लगाकर स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा था। न्यूनतम किराया 30 रुपए लिया जा रहा था। अब उन ट्रेनों को सामान्य पैसेंजर कर दिया गया है। अब यात्रियों को न्यूनतम किराया 10 रुपए ही देना पड़ेगा। दानापुर रेलमंडल में ऐसी 78 पैसेंजर ट्रेनें हैं। एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में सफर करने का न्यूनतम किराया 30 रुपए है। ऐसे में पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों का न्यूनतम किराया बराबर हो गया था। जिन पैसेंजर ट्रेनों के नंबर के पहले जीरो नहीं लगा था, उनमें न्यूनतम किराया 10 रुपए ही लिया जा रहा था। हालांकि तीन पैसेंजर ट्रेनों में नंबर के पहले जीरो तो लगा लेकिन इनके किराया में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया। डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था 10 मार्च, 2024 से ही लागू कर दी गई है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.3.24)

1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मजदूरी की दरें (अनुसूची-II)

क्र. सं.	कामागारों की कोटि	दिनांक 01.09.2022+01.10.2022+ 01.04.2023+01.10.2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी होगी	01.04.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00=395.00	15.00	410.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00=411.00	15.00	426.00 प्रतिदिन
3	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00=500.00	19.00	519.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00=611.00	23.00	634.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	10478+210.00+419.00+419.00+ 210.00=11317.00	419.00	11736.00 प्रतिमाह

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296